पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मुख्यमंत्री ने स्टेट ट्रान्सफॉर्मेशन कमीशन की बैठक (सी0एम0–समीक्षा) में विकास परियोजनाओं तथा जनकल्याणकारी योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की

बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास और लोककल्याण से जुड़ी समस्त परियोजनाओं को निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाए : मुख्यमंत्री

ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की वित्तीय बिड अगले दो सप्ताह में खोलने और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की कार्यवाही तेज करने के निर्देश

नगरीय क्षेत्रों में निर्माणाधीन 8 वर्किंग विमेन हॉस्टल (नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद) के कार्यों में तेजी लाने तथा 13 जनपदों में प्रस्तावित नए हॉस्टलों के लिए भारत सरकार के सम्बन्धित विभाग से समन्वय बनाए रखने के निर्देश

श्रमिकों को मौके पर ही श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, रियायती भोजन और निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश

'जीरो पावर्टी योजना' के अन्तर्गत चिन्हित 12.50 लाख परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने पर विशेष बल

उद्योगों, निजी क्षेत्र तथा निवेशकों को मिलने वाली रियायतों और सुविधाओं के माध्यम से सृजित होने वाले रोजगार तथा अन्य सभी लाभों का सीधा लाभ प्रदेश के युवाओं और स्थानीय नागरिकों को प्राप्त हो

नई व्यवस्था के तहत आउटसोर्सिंग कार्मिकों के मानदेय में बढ़ोतरी का लाभ समस्त विभागों में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी को प्रत्येक दशा में मिले

डिजिटल लाइब्रेरी के लिए कम्प्यूटर हार्डवेयर की आपूर्ति तत्काल पूर्ण की जाए

लखनऊ : 22 नवम्बर, 2026

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल तैयार किया है। उद्योगों, निजी क्षेत्र तथा निवेशकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, टैक्स रियायतें और सब्सिडी प्रदान की जा रही हैं। सरकार की प्रत्येक नीति, निर्णय और प्रावधान के केन्द्र में प्रदेश की जनता का हित निहित है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इन रियायतों और सुविधाओं के माध्यम से सृजित होने वाले रोजगार तथा अन्य सभी लाभों का सीधा लाभ प्रदेश के युवाओं और स्थानीय नागरिकों को प्राप्त हो।

मुख्यमंत्री जी आज अपने सरकारी आवास पर आहूत स्टेट ट्रान्सफॉर्मेशन कमीशन की बैठक (सी0एम0–समीक्षा) में प्रदेश में संचालित और प्रस्तावित विकास परियोजनाओं तथा जनकल्याणकारी योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास और लोककल्याण से जुड़ी समस्त परियोजनाओं को निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाए। इस अवसर पर स्टेट ट्रान्सफॉर्मेशन कमीशन के सी0ई0ओ0 श्री मनोज कुमार सिंह ने विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति का प्रस्तुतीकरण दिया।

मुख्यमंत्री जी ने आउटसोर्सिंग कार्मिकों के हितों को लेकर निर्देश दिए कि राज्य सरकार द्वारा नई व्यवस्था के तहत आउटसोर्सिंग कार्मिकों के मानदेय में जो बढ़ोतरी की गई है, उसका लाभ समस्त विभागों में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी को प्रत्येक दशा में मिलना चाहिए। प्रदेश के 88 विभागों में तैनात 3,10,437 आउटसोर्सिंग कार्मिकों के मानदेय भुगतान की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक कार्मिक को उसका बढ़ा हुआ मानदेय समय पर और पूरा प्राप्त हो। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैठक में एक्सप्रेस–वे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री जी को अगवत कराया गया कि चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस–वे की निविदा प्रक्रिया को आगामी 30 नवम्बर तक अन्तिम रूप दे दिया जाएगा। फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस–वे के लिए 91.46 प्रतिशत भूमि का क्रय पूर्ण हो चुका है और चयनित फर्म को एल0ओ0ए0 जारी कर दिया गया है। इसी प्रकार आगरा–लखनऊ–पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस–वे के लिए 82.98 प्रतिशत, झाँसी लिंक एक्सप्रेस–वे के लिए 86.04 प्रतिशत तथा जेवर लिंक एक्सप्रेस–वे के लिए 83.45 प्रतिशत भूमि प्राप्त कर ली गई है।

इन तीनों परियोजनाओं में भी निर्माण हेतु चयनित फर्मों को एल0ओ0ए0 जारी किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त मेरठ–हरिद्वार, विंध्य एक्सप्रेस–वे और विंध्य–पूर्वांचल स्पर के सत्यापन का कार्य पूर्ण हो चुका है। अधिकांश जनपदों में भूमि दरों का अनुमोदन कर दिया गया है, जिस पर शीघ्र भूमि अधिग्रहण प्रारम्भ करने के

निर्देश दिए गए हैं। औद्योगिक विकास से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के लिए प्राप्त निविदाओं की वित्तीय बिड अगले दो सप्ताह में खोलने और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आगे की कार्यवाही तेज करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए 'जीरो पावर्टी योजना' के अन्तर्गत चिन्हित 12.50 लाख परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने पर विशेष बल दिया। बैठक में बताया गया कि पात्र परिवारों में से 59,447 पी0एम0/सी0एम0 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। आयुष्मान कार्ड से वंचित परिवारों के लिए बी0ओ0सी0डब्ल्यू0 के माध्यम से पंजीकरण कर अब तक 1,04,583 परिवारों को आयुष्मान कार्ड से संतृप्त किया गया है, जबकि शेष पात्र परिवारों के आयुष्मान और अन्त्योदय कार्ड बनाने की कार्यवाही युद्धस्तर पर जारी है।

इसके अतिरिक्त 10.60 लाख परिवारों के एक–एक सदस्य को कौशल प्रशिक्षण देने के तहत अब तक 11,298 युवाओं को प्रशिक्षित और सेवायोजित किया गया है, जिसमें और तेजी लाने के निर्देश दिए गए। श्रम विभाग की समीक्षा में बताया गया कि 01 सितम्बर, 2026 से अब तक प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लेबर अड्डों पर 8,950 कैम्प लगाकर 2,73,391 श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने श्रमिकों को मौके पर ही श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, रियायती भोजन और निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने नगरीय क्षेत्रों में महिला श्रम भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्माणाधीन 8 वर्किंग विमेन हॉस्टल (नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद) के कार्यों में तेजी लाने को कहा। साथ ही, सी0एम0–डब्ल्यू0डब्ल्यू0एच0 योजना के तहत 13 जनपदों में प्रस्तावित नए हॉस्टलों के लिए भारत सरकार के सम्बन्धित विभाग से निरन्तर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायतों में स्थापित हो रही 11,350 डिजिटल लाइब्रेरी की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि शेष पंचायतों में कम्प्यूटर हार्डवेयर की आपूर्ति तत्काल पूर्ण की जाए।

बुनियादी ढांचे और सिंचाई सम्बन्धी परियोजनाओं की समीक्षा में लोक निर्माण विभाग की 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 279 परियोजनाओं (कुल लागत 47,248 करोड़ रुपये) को निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। गड्ढा मुक्ति अभियान के तहत प्रदेश में 54,878 किलोमीटर के लक्ष्य के सापेक्ष 50,189 किलोमीटर (91 प्रतिशत) मार्गों की मरम्मत पूर्ण होने पर संतोष व्यक्त करते हुए शेष सड़कों को तत्काल गड्ढामुक्त करने को कहा गया।

सिंचाई विभाग की 23 बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण), हस्तिनापुर तटबन्ध और सिंहवाहिनी पम्प नहर परियोजना को शीघ्र लोकार्पण के लिए तैयार करने तथा 1,750 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण और सरयू नहर व अर्जुन सहायक परियोजना के अवशेष कार्यों को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

————————

PN-CM-State Transformation Commission -22 November, 2026